The Maulana Azad Education Foundation was set up for the purpose of promotion of educational activities among educationally backward sections of the society particularly the minorities.

The Ministry of HRD Deptt. of Education has been implementing three separate schemes for the educational development of minorities in the minority concentration districts under the Programme of Action prepared in pursuance of National Policy on Education. The schemes are Area Intensive Programme, Modernisation of Madarsa Education and Community Polytechnics. The University Grants Commission is implementing a coaching scheme for minority candidates through the various Universities and Colleges. Under the UGC Coaching scheme candidates are provided free stipendary coaching.

(b) No other special incentives to Minorities other than the schemes and programmes at (a) are under the consideration of the Govt, at present.

(c) Does not arise.

Steel plants in private and public sectors

536. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the number of steel plants set up by the private and public sectors at different places in the country;

(b) whether it is a fact that the steel plants whether in private or public sector are not taking any interest in the development of ancillary units; and

(c) if so, the steps taken by Government for making all the steel plants mandatory to develop the ancillary units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) There are 6 integrated steel plans in the public sector and 1 in the private sector.

(b) No, Sir.

(p) Does not arise in view of (b).

Establishment of pig iron plants in Orissa

537. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether there is a vast scope for the establishment of pig iron plants in Orissa;

(b) if so, the number of pig iron plants proposed to be set up in that State;

(c) the places identified for the location of pig iron plants in that State; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) The scope for pig iron plants in Orissa would depend on a large number of factors viz. availability and price of required grade of raw-materials, infrastructural facilities, availability and cost of financing, cost competitiveness of the product, market conditions etc. Investment would depend upon an appraisal of above factors by interested entrepreneurs and their commercial judgements.

(b) to (d) According to information made available by the State Govt, of

Orissa, the following two pig iron plants are proposed to "be set up in Orissa:

S. No.	Name of the Unit	Location	Capacity	Project Cost
1.	M/s Mideast Integrated Steel Ltd.	Integrated Indl. Complex, Buburi.	0.50 MTPY pig iron (in 1st phase)	Rs. 310 Crs.
2.	M/s Neelachal Ispat Nigam Limited.	-do-	1.0 MTPY pig iron (in 1st Phase)	NA

स्थानीय विकास के लिए निधि का आवंटन

538. **श्री अजीत जोगी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है,

(ख) उसका विशेष योजनावार ब्यौरा क्या है,

(ग) उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) चालू योजनाआवधि के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और पहेल तीन वर्षो के दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा देश के सभी विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्वरोजगार गरीब परिवारों को ऋण प्रदान करके उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां प्राप्त कराके उन्हें अपनी आय को बढ़ाने और गरीबी की रेखा को पार करने के योग्य बनाना है ताकि उन्हें सतत आधार पर स्वरोजगार मिलता रहे। आय सृजित करने की गतिविधियां शुरू करने हेतु सबसिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इस योजना के अतंर्गत, खर्च को केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। दूसरी तरफ, जवाहर रोजगार योजना एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार पैदा करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कुल खर्च को केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के आधार पर वहन किया जाता है। गैर-कृषि मौसम के दौरान बेरोजगार वयस्कों के लिए सुनिश्चित रोजगार की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने देश के चयनित खण्डों में अक्टूबर 93 से सुनिश्चित रोजगार योजना को शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं और जो काम की तलाश में हैं को सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, केन्द्र देश के सभी गांवों/वसावटों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए राज्यों को निधियां रिलीज करता है। राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मैचिंग अनुदान भी दिया जाता है।

1995-96 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के कुल आंवटन को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण – 1 पर दिया गया है (**नीचे देखिए**)

(घ) 1992-93 से 1994-95 के दौरान सूचित खर्च के साथ-साथ चालू योजना अवधि के लिए आवंटित की गई कुल राशि को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण – 2 पर दिया गया है (नीचे देखिए)।